

सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। कठिनाइयाँ केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेने आती हैं, आपको रोकने नहीं।

# परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 395, नई दिल्ली, शनिवार 04 अप्रैल 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 महादेव क्यों कहलाए अर्धनारीशंकर

06 सुनहरे गेहूँ की कहानी: प्राचीन रीति-रिवाजों से लेकर मशीन युग ...

08 2027 के चुनावों में मान सरकार के पक्ष में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 सीटों ...

## सम्मान की गौरवशाली परंपरा: जब कर्मयोगियों के द्वार पुनः पहुँचे संपादक संजय बाटला; 'परिवहन विशेष' ने देश के नायकों को सराहा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: पत्रकारिता के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को जीवंत रखते हुए 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र ने एक नई मिसाल पेश की है। समाचार पत्र के तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह के उपरांत, मुख्य संपादक संजय बाटला उन गणमान्य विभूतियों के द्वार जाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, जो अपनी व्यस्तता के कारण मुख्य आयोजन में शिरकत नहीं कर पाए थे।

**न्याय, प्रशासन और समाजसेवा के स्तंभों का सम्मान**  
इसी कड़ी में आज मुख्य संपादक संजय बाटला अपनी टीम के साथ विशिष्ट न्यायविदों, अधिवक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के निवास पर पहुँचे। उन्होंने निम्नलिखित हस्तियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया:

**माननीय न्यायमूर्ति राजेश टंडन:** पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश, दैनिक लोक अदालत, नैनीताल (UK)। आपको आपके दीर्घकालीन न्यायिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

**श्री आलोक कुमार:** मुख्य महाप्रबंधक (LPG - सेवानिवृत्त), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (विपणन प्रभाग), दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में आपकी प्रबंधकीय सेवाओं को सराहा गया।

**श्री के.सी. बजाज:** उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सुप्रीम कोर्ट) के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल। आप मूल रूप से हिसार, हरियाणा से संबंध रखते हैं।

**संध्या बजाज:** उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य। आप

हरियाणा हैंडलूम एपेक्स की पूर्व चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की पूर्व निदेशक एवं भाजपा हरियाणा की पूर्व प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बच्चों के अधिकारों और समाज कल्याण के क्षेत्र में आपकी सक्रियता प्रेरणादायक है।

**पहल की सराहना**

इस विशेष अभियान के दौरान मुख्य संपादक के साथ वरिष्ठ समाजसेविका पिंकी कुंडू जी भी उपस्थित रहीं। सम्मानित हस्तियों ने 'परिवहन विशेष' की इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्यस्थल या निवास पर जाकर सम्मान देना न केवल गौरव की बात है, बल्कि यह समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। अंत में सभी ने समाचार पत्र के उज्ज्वल भविष्य और निर्भीक पत्रकारिता की कामना की।

**"सम्मान केवल मंच का मोहताज नहीं होता, वह व्यक्तित्व की गरिमा को पहचानने का नाम है।"**

- संजय बाटला

“सम्मान केवल एक मंच या भव्य आयोजन का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह उन प्रयासों की स्वीकृति है जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। हमारे ये गणमान्य अतिथि अपनी प्रशासनिक और सामाजिक व्यस्तताओं के कारण मुख्य समारोह में नहीं आ सके, लेकिन उनके द्वारा देशहित में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का मूल्य कम नहीं हो जाता। 'परिवहन विशेष' परिवार का यह सौभाग्य है कि हमें आज इन कर्मयोगियों के द्वार पर आकर उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। राष्ट्र निर्माण में इन अधिकारियों और जनाप्रतिनिधियों का योगदान अतुलनीय है और हमें उम्मीद है कि इनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहेगा।”

### न्यायमूर्ति राजेश टंडन के निवास पहुँचे संपादक संजय बाटला; सम्मान के साथ हुआ रात्रि सह-भोज

सामाजिक सरोकारों को जीवंत रखते हुए 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र ने एक नई मिसाल पेश की है। इसी कड़ी में मुख्य संपादक संजय बाटला ने अपनी टीम के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश (दैनिक लोक अदालत, नैनीताल) माननीय न्यायमूर्ति राजेश टंडन के निवास पर पहुँचकर उन्हें

सम्मानित किया। न्यायमूर्ति टंडन को उनके दीर्घकालीन और विशिष्ट न्यायिक योगदान के लिए 'परिवहन विशेष' सम्मान पत्र भेंट किया गया। सम्मान की यह औपचारिक मुलाकात उस समय और भी यादगार हो गई, जब न्यायमूर्ति जी के निवास पर रात्रि सह-भोज (Dinner) का आयोजन हुआ। इस दौरान न्यायिक जगत, पत्रकारिता और सामाजिक

विषयों पर गहन चर्चा हुई। संजय बाटला ने कहा कि जस्टिस टंडन जैसी महान विभूतियों का सान्निध्य मिलना गर्व की बात है। न्यायमूर्ति जी ने 'परिवहन विशेष' की इस आत्मीय पहल की सराहना करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेविका पिंकी कुंडू आदि उपस्थित रहीं।



**श्री आलोक कुमार:** मुख्य महाप्रबंधक (LPG - सेवानिवृत्त), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (विपणन प्रभाग), दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में आपकी प्रबंधकीय सेवाओं को सराहा गया।

**श्री के.सी. बजाज:** उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सुप्रीम कोर्ट) के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल।

**संध्या बजाज:** उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य। आप हरियाणा हैंडलूम एपेक्स की पूर्व चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की पूर्व निदेशक एवं भाजपा हरियाणा की पूर्व प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

**सड़क सुरक्षा का संदेश, नन्हें कदमों के संग!** 6 वर्षीय नील कुंडू और 4 वर्षीय गिरिक कुंडू ने अपनी कविता के माध्यम से सड़क सुरक्षा (Road Safety) के प्रति जागरूकता फैलाने की एक अद्भुत कोशिश की है। इन नन्हें 'परिवहन प्रहरी' के जन्म को हमारा सलाम!



## टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

<https://tolwa.com/about.html> |  
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

## आज का साइबर सुरक्षा विचार : कंबोडिया के स्कैम हब्स से चल रहे धोखाधड़ी तंत्र को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश है।

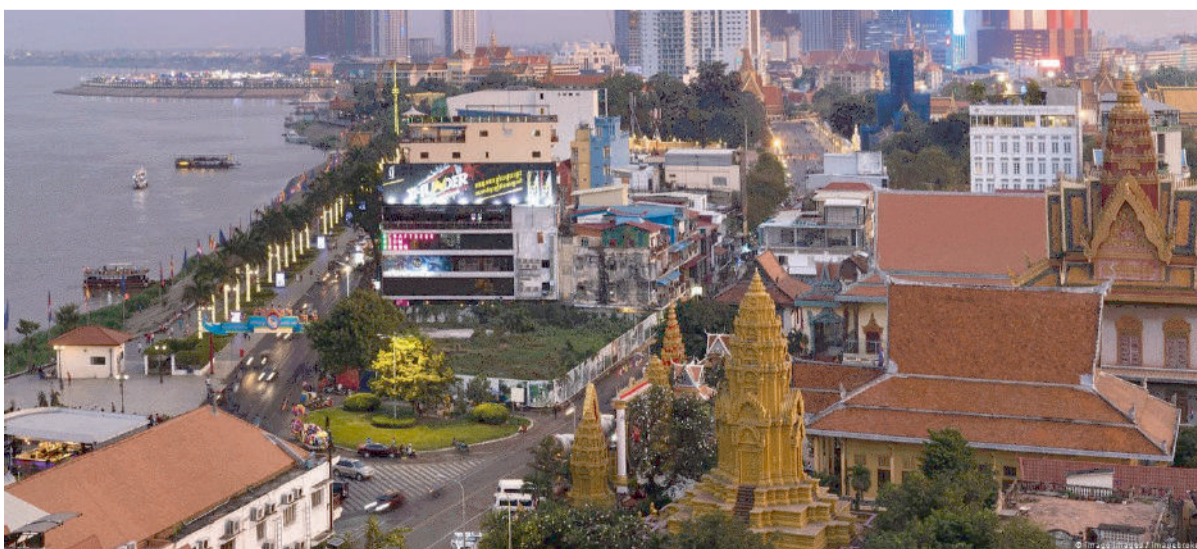


पिंकी कुंडू

सक्रिय SIM कार्डों के साथ पकड़ा गया।

**SIM कार्ड रिकेट की कार्यप्रणाली (Modus Operandi)**

- SIM कार्ड की खरीद**
  - हैदराबाद और अन्य क्षेत्रों के स्थानीय विक्रेता बड़ी संख्या में SIM कार्ड जुटाते थे।
  - नकली दस्तावेज और पहचान का उपयोग कर इन्हें सक्रिय किया जाता था, जिससे KYC नियमों को दरकिनार किया गया।
- पूर्व-सक्रियण और भंडारण**
  - SIM कार्ड भारत में ही सक्रिय कर दिए जाते थे।
  - गिरफ्तारी के समय एक आरोपी के पास 198 सक्रिय SIM कार्ड मिले।
- कंबोडिया तक**
  - कुरियर SIM कार्डों को बैंग में छिपाकर RGIA, रामशाबाद



से उड़ान भरने की कोशिश करते।

- इमिग्रेशन अधिकारियों को सूचना पर TGCSB ने कार्रवाई की।

**कंबोडिया और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई स्कैम हब्स तक पहुँचाए जाते।**

- वहाँ इन्हें संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट्स को सौंप दिया जाता।

**स्कैम इंफ्रास्ट्रक्चर**

- कंबोडिया में SIM कार्ड SIM Banks/SIM Boxes में लगाए जाते, जो एक साथ सैकड़ों SIM चला सकते हैं।
- इनसे बड़े पैमाने पर

कॉल, OTP रिक्वेस्ट और फिशिंग मैसेज भेजे जाते, जो भारतीय नंबर से आते हुए प्रतीत होते।

**धोखाधड़ी का निष्पादन**

- भारत में पीड़ितों को

कॉल/SMS मिलता जो वैध भारतीय नंबर जैसा दिखता।

- प्रमुख धोखाधड़ी:
  - फिशिंग लिंक (नकली बैंकिंग/पेमेंट पोर्टल)
  - फर्जी कॉल (पुलिस, बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर)
  - OTP चोरी कर अकाउंट पर कब्जा
  - स्पूफ़ नंबर से वसूली और धमकी
- धोखाधड़ी का पैमाना**
  - TGCSB ने बताया कि 2025 में पूरे भारत में 24 लाख पीड़ितों ने ₹22,000 करोड़ गँवाए, जिनमें से कई मामले विदेशी सिंडिकेट्स द्वारा भारतीय SIM के इस्तेमाल से जुड़े थे।
- प्रमुख गिरफ्तारियाँ
  - सैयद अशरफ अली, चंद्रानगुडा, हैदराबाद का SIM विक्रेता, मुख्य आरोपी था।
  - वह और उसके चार साथी

SIM कार्ड कंबोडिया भेजने की कोशिश में पकड़े गए।

- जोखिम और प्रभाव**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा: भारतीय SIM विदेश में जाकर धोखेबाजों को घरेलू कॉलर जैसा दिखने देता है।
  - आर्थिक नुकसान: नागरिकों से करोड़ों रुपये ठगे गए।
  - नियामक खामियाँ: KYC नियमों की कमजोर निगरानी का फायदा उठाया गया।
  - सुझाव/एगरोकथाम उपाय
    - टेलीकॉम कंपनियों द्वारा SIM KYC नियमों का सख्ती से पालन हो रोकथाम का प्रभावी उपाय है।
    - देश की अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस कार्यप्रणाली के मद्देनजर अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर ऐसे और भी सिंडिकेट्स का पता लगाकर उनका पर्दाफाश करना चाहिए।

# स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

## भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि

डॉ. शैलेश शुक्ला

भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग 142.8 करोड़ आंकी गई, जिससे वह चीन से आगे निकल गया। यह स्थिति केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि या वैश्विक रैंकिंग का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के संसाधनों, प्रशासनिक क्षमता, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव डालने वाली वास्तविकता है। लंबे समय तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को विकास की शक्ति और श्रमबल की उपलब्धता के रूप में देखा जाता रहा, किंतु जैसे-जैसे जनसंख्या का दबाव भूमि, जल, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर बढ़ा, यह स्पष्ट होता गया कि अनियंत्रित वृद्धि देश को अनेक जटिल समस्याओं को जन्म दे रही है या उन्हें और गंभीर बना रही है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप जटिल है, क्योंकि एक ओर कुल जनसंख्या में गिरावट देखी

जा रही है, तो दूसरी ओर जनसंख्या का कुल आकार इतना विशाल है कि प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों की वृद्धि अभी भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 2.0 के आसपास आ चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, फिर भी जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी क्योंकि देश में प्रजनन आयु वर्ग की आबादी अत्यधिक बढ़ी है। इस स्थिति को जनसांख्यिकीय जड़त्व या पॉपुलेशन मोमेंट कहा जाता है, जिसके कारण प्रजनन दर घटने के बावजूद कुल जनसंख्या बढ़ती रहती है। यही कारण है कि भारत की समस्याओं का संबंध केवल जन्मदर से नहीं, बल्कि पहले से मौजूद विशाल जनसंख्या आधार से भी है।

भारत की आर्थिक चुनौतियों को समझने में जनसंख्या का प्रभाव सबसे स्पष्ट रूप से रोजगार क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ष लाखों युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं, किंतु उद्योग, सेवा और कृषि क्षेत्र इतने रोजगार सृजित नहीं कर पाते कि सभी को समुचित अवसर मिल सके। परिणामस्वरूप बेरोजगारी और अधरोजगारी दोनों

बढ़ती हैं, जिससे सामाजिक असंतोष, प्रवासन और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ जाती है। जब श्रम की आपूर्ति अत्यधिक हो और अवसर सीमित हों, तो मजदूरी का स्तर भी दबाव में रहता है, जिससे गरीबी उन्मूलन की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार जनसंख्या का दबाव सीधे-सीधे आर्थिक असमानता और रोजगार संकट से जुड़ जाता है।

शिक्षा व्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। देश में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संस्थानों की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन छात्र संख्या की तुलना में संसाधन अभी भी अपर्याप्त हैं। अनेक सरकारी विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात मानकों से अधिक है, कक्षाओं में भीड़ है और बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रहती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि लाखों योग्य छात्र सीटों के अभाव में वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत अवसरों को सीमित नहीं करती, बल्कि देश की मानव संसाधन क्षमता को भी प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव

और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अस्पतालों में भीड़, चिकित्सकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और सरकारी योजनाओं के सीमित संसाधन—ये सभी समस्याएँ उस स्थिति से जुड़ी हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि की गति के अनुरूप स्वास्थ्य अवसरों का विस्तार नहीं हो पाता।

भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर चिकित्सकों और अस्पताल बेड की संख्या अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसे में महामारी या आपात स्थितियों में स्वास्थ्य तंत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था।

जनसंख्या वृद्धि का सबसे गंभीर प्रभाव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। भूमि सीमित है, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे कृषि भूमि का विभाजन होता है, शहरीकरण बढ़ता है और जंगलों पर दबाव पड़ता है। जल संसाधनों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पिछले दशकों में तेजी से घटी है और कई शहरों में जल संकट नियमित समस्या बन चुका है। जब अधिक लोग सीमित

संसाधनों पर निर्भर होते हैं, तो पर्यावरणीय क्षरण, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएँ भी तीव्र हो जाती हैं।

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव अव्यवस्थित विस्तार, झुग्गी बस्तियों की वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की कमी के रूप में दिखाई देता है। रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है, जिससे शहरों की जनसंख्या उनकी नियोजित क्षमता से अधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़, सार्वजनिक परिवहन पर दबाव, कचरा प्रबंधन की समस्या और आवास संकट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यह केवल शहरी प्रशासन की विफलता नहीं, बल्कि जनसंख्या और संसाधनों के असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

भारत में गरीबी और जनसंख्या वृद्धि के बीच गहरा संबंध है। जिन परिवारों की आय कम होती है, उनमें बच्चों की संख्या अधिक होने की प्रवृत्ति लंबे समय तक देखी गई है, जिससे संसाधनों का विभाजन और भी अधिक हो जाता है। हालांकि हाल

के वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण यह प्रवृत्ति बदल रही है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में उच्च जन्मदर अभी भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या नियंत्रण केवल स्वास्थ्य या परिवार नियोजन का विषय नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विकास का प्रश्न भी है।

यह भी सत्य है कि जनसंख्या को केवल समस्या के रूप में देखना पूर्णतः उचित नहीं है। विशाल जनसंख्या भारत के लिए एक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश भी है, क्योंकि देश में कार्यशील आयु वर्ग की संख्या बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच है, जो आर्थिक विकास के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। किंतु यह लाभांश तभी वास्तविक संपदा बन सकता है जब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। अन्यथा यही युवा जनसंख्या सामाजिक असंतोष और आर्थिक दबाव का कारण बन सकती है।

## शुगर में ध्यान रखने योग्य बातें

पिकी कुंडू

शुगर (डायबिटीज) को कंट्रोल करने के लिए दवाएँ/गोलियाँ बहुत जरूरी हैं। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल या डॉक्टर की सलाह के बिना लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं।

शुगर की गोलियों के ज्यादा इस्तेमाल के साइड इफेक्ट

1. लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसेमिया) चक्कर आना पसीना आना हाथ काँपना बेहोशी यह सबसे खतरनाक असर हो सकता है
2. पेट की समस्याएँ मतली, उल्टी डायरिया पेट दर्द (खासकर मेटफॉर्मिन जैसी कुछ दवाएँ लेने के बाद)
3. वजन बढ़ना कुछ गोलियाँ वजन बढ़ाती हैं (इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाओं के कारण)
4. किडनी पर असर ज्यादा दवाएँ किडनी पर दबाव डाल सकती हैं, अगर पहले से किडनी की कोई समस्या है तो खतरा बढ़ जाता है
5. लिवर पर असर कुछ दवाएँ लिवर पर असर डालती हैं, लंबे समय तक ज्यादा

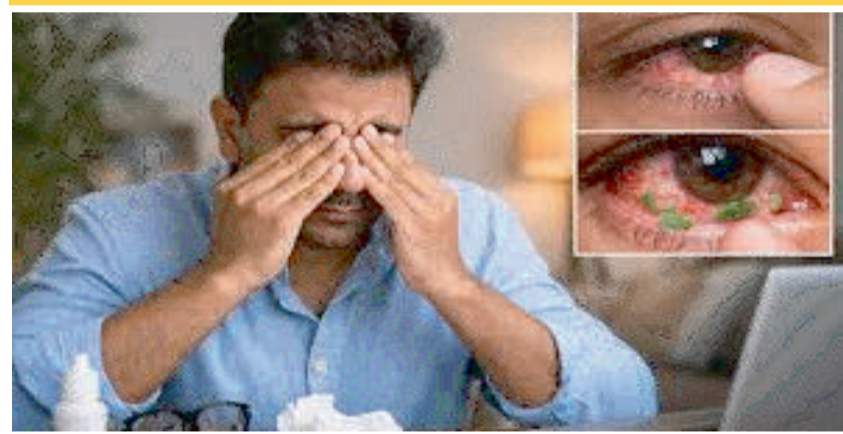


इस्तेमाल से लिवर डैमेज हो सकता है

6. विटामिन की कमी मेटफॉर्मिन का लंबे समय तक इस्तेमाल विटामिन B12 कम कर सकता है, इससे हाथ-पैरों में कमजोरी, सुन्नपन हो सकता है
7. दिल पर असर (कुछ दवाओं में) कुछ पुरानी दवाएँ दिल के लिए खतरनाक हो सकती हैं किन बातों का ध्यान रखें? डॉक्टर की सलाह के बिना डोज न बढ़ाएं दवाएँ समय पर लें

शुगर रेगुलर चेक करें डाइट + एक्सरसाइज पर ध्यान दें जरूरी सलाह:- शुगर की गोलियाँ अचानक बंद करना या बहुत ज्यादा लेना, दोनों ही खतरनाक हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से इलाज करें।

## क्या आपको अपनी आँखें रगड़ने की आदत है? आज ही बंद करें!



पिकी कुंडू

अपनी आँखों को बार-बार रगड़ना एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं: अपनी आँखों को जोर से रगड़ना

1. कॉर्निया को नुकसान पहुँचा सकता है
2. केराटोकोनस (आँखों के आकार में बदलाव) हो सकता है
3. आँखें लाल हो जाती हैं, सूजन बढ़ जाती है अपनी आँखों को गंदे हाथों से रगड़ना

2. कंजंक्टवाइटिस (आँखों का इन्फेक्शन) हो सकता है तो क्या करें? अगर आपकी आँखों में खुजली हो:- ठंडे पानी से सिकाई करें अगर आपको सूखापन महसूस हो:- आई ड्रॉप्स (लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स) का इस्तेमाल करें \* हमेशा अपने हाथ साफ़ करें \* अपनी आँखों को धीरे से छुएँ अगर समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें - इसे नज़रअंदाज न करें!

## सुबह की धूप – नेचुरल दवा!



पिकी कुंडू

सूरज निकलने से लेकर सुबह करीब 7 से 9 बजे तक की धूप शरीर के लिए अमृत जैसी होती है

सुबह की धूप के कमाल के फायदे

- \* हड्डियाँ मजबूत होती हैं
- \* विटामिन D बनता है,
- \* कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है
- \* जोड़ों, घुटनों और पीठ के दर्द को कम करने में मदद करता है
- \* कमजोरी दूर करता है
- \* शरीर में तनूजी बढ़ाता है
- \* थकान, कमजोरी कम होती है
- \* मन खुश रहता है

- \* स्ट्रेस कम होता है
- \* मूड फ्रेश रहता है
- \* नींद बेहतर होती है
- \* बाँड़ी क्लॉक (स्लीप साइकिल) सही रहती है
- इसे कितनी देर लेना चाहिए?
- \* रोजाना 15-20 मिनट काफी हैं
- \* समय: सुबह 7 से 9 बजे
- इसे कैसे लें?
- \* अपना चेहरा, हाथ और पैर धूप में रखें
- \* टहलें / प्राणायाम करें
- \* बिना सनस्क्रीन/क्रीम लगाए धूप में निकलें
- इन गलतियों से बचें
- \* 10 के बाद तेज धूप
- \* कांच से आती धूप (विटामिन D नहीं देती)

- \* देर तक धूप में बैठना धूप + सही डाइट = डबल फायदा
- \* कैल्शियम: दूध, तिल, रागी
- \* विटामिन D: अंडे, फोर्टिफाइड दूध
- \* प्रोटीन: दाल, पनीर
- किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है?
- \* जोड़ों का दर्द
- \* पीठ दर्द
- \* घुटने का दर्द
- \* कमजोरी
- \* विटामिन D की कमी वाले लोग रोजाना धूप + डाइट + हल्की एक्सरसाइज = 80% समस्या नेचुरली कंट्रोल हो जाती है

## भारत में व्यापक सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी: एक मौक स्वास्थ्य संकट

भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, लेकिन इसके भीतर एक गंभीर और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला स्वास्थ्य संकट छिपा हुआ है — **विटामिन D, विटामिन B12, प्रोटीन और कैल्शियम की व्यापक कमी।**

यह समस्या केवल गरीब या कुपोषित वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी, शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग भी इससे उतना ही प्रभावित है।

1. विटामिन D की कमी — धूप के देश में एक विडंबना

भारत जैसे धूप-प्रधान देश में विटामिन D की कमी होना अपने आप में चौकाने वाला तथ्य है।

अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 70% से 90% भारतीयों में विटामिन D का स्तर सामान्य से कम है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।

बड़े पैमाने पर किए गए विश्लेषण (जैसे Tata 1mg के 2.2 लाख से अधिक लोगों के डेटा) बताते हैं कि लगभग 75-80% वयस्कों में विटामिन D की कमी पाई गई, और सबसे अधिक प्रभावित वर्ग 25 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। इसके प्रमुख कारण:

इनडोर जीवनशैली: दफ्तरों में लंबे समय तक रहना, ऊँची इमारतों में रहना, स्क्रीन-आधारित जीवन।

वायु प्रदूषण: UVB किरणों को रोक देता है, जो त्वचा में विटामिन D बनने के लिए आवश्यक है।

गहरी त्वचा का रंग और पारंपरिक वस्त्र, जिससे त्वचा पर धूप कम पड़ती है।

आहार में कमी: मछली, अंडा, फोर्टिफाइड दूध जैसे प्राकृतिक स्रोतों का सीमित सेवन।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: विटामिन D केवल हड्डियों तक सीमित नहीं है। इसकी कमी से: ऑस्टियोपोरोसिस और रिफ्रेक्टस मांसपेशियों की कमजोरी, थकान रोग-प्रतिरोधक क्षमता में कमी अवसाद, मधुमेह, हृदय रोग कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम तक बढ़ जाता है।



2. विटामिन B12 की कमी — व्यापक लेकिन उपेक्षित विटामिन B12 की कमी भारत में स्थानिक (Endemic) बन चुकी है।

विभिन्न शोधों के अनुसार 40% से 70% भारतीयों में B12 की कमी पाई जाती है।

सीमांत (borderline) मामलों को जोड़ने पर यह आँकड़ा 60-70% तक पहुँच जाता है।

शहरी पेशेवरों पर किए गए एक अध्ययन में 57% पुरुष और लगभग 50% महिलाएँ B12 की कमी से ग्रस्त पाई गईं।

इतनी व्यापक क्यों है यह समस्या? आहार कारण: विटामिन B12 मुख्यतः पशु-आधारित खाद्य पदार्थों (मांस, मछली, अंडा) में पाया जाता है।

भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है, जिससे प्राकृतिक B12 का सेवन बहुत कम हो जाता है।

अवशोषण की समस्या: पाचन संबंधी रोग, उम्र बढ़ना और कुछ दवाओं का लंबे समय तक सेवन B12 के अवशोषण को बाधित करता है।

इसके गंभीर प्रभाव: एनीमिया (खून की कमी) अत्यधिक थकान याददाश्त और आक्रामता में कमी

हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नता लंबे समय तक कमी रहने पर स्थायी तंत्रिका क्षति

3. प्रोटीन और कैल्शियम — कम चर्चा, बड़ा असर हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चा कम होती है, लेकिन:

बड़ी संख्या में भारतीय, विशेषकर महिलाएँ, बच्चे और निम्न-आय वर्ग, अनुशंसित मात्रा (RDA) से कम प्रोटीन और कैल्शियम लेते हैं।

यह स्थिति: विटामिन D की कमी के प्रभाव को और बढ़ा देती है

हड्डियों को कमजोर बनाती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ाती है

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव यह पोषण संकट जीवन के हर चरण को प्रभावित करता है।

अल्पकालिक प्रभाव: थकान मांसपेशियों की कमजोरी मूड स्विंग्स

ध्यान और सोचने की क्षमता में कमी बच्चों में विकास में देरी और हड्डियों की विकृति (रिकेट्स)

दीर्घकालिक खतरें: वृद्धावस्था में हड्डियाँ टूटने का उच्च जोखिम

तंत्रिका तंत्र को स्थायी नुकसान मधुमेह, हृदय रोग जैसे गैर-संचारी रोगों का बढ़ता खतरा

5. भारत में यह समस्या इतनी व्यापक क्यों है? इस विरोधाभास के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं:

जीवनशैली और शहरीकरण

आधुनिक जीवनशैली ने हमें धूप और शारीरिक गतिविधि दोनों से दूर कर दिया है।

आहार संबंधी आदतें शाकाहार प्रधान आहार + कम फोर्टिफाइड भोजन = B12 और प्रोटीन की कमी।

जागरूकता और जांच की कमी अधिकांश लोग तब तक जांच नहीं कराते जब तक लक्षण गंभीर न हो जाएँ।

नीतिगत कमी नमक में आयोडीन की तरह विटामिन D और B12 के लिए कोई राष्ट्रीय फोर्टिफिकेशन नीति अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं है।

6. हालिया रुझान और प्रयास स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब इसे "मौक महामारी" कह रहे हैं।

बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग, जन-जागरूकता और फोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों की माँग बढ़ रही है।

मीडिया और अकादमिक जगत में समय पर पहचान, संतुलित आहार और सुरक्षित सप्लीमेंटेशन पर जोर दिया जा रहा है।

7. सारांश (Key Takeaways) पोषक तत्व भारत में अनुमानित कमी

मुख्य कारण प्रमुख प्रभाव विटामिन D 70-90% कम धूप, प्रदूषण कमजोर हड्डियाँ, थकान विटामिन B12 40-70% शाकाहार

आहार गुणवत्ता आहार गुणवत्ता मांसपेशी व हड्डी कमजोरी

व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है?

\* समय-समय पर रक्त जांच कराएँ \* रोजाना 15-20 मिनट सुरक्षित धूप लें

\* आहार में प्रोटीन और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल करें

\* डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।



## आमजन की प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान करें अधिकारी : डीसी

समाधान शिविरों में अभी तक कुल शिकायतें 5789 प्राप्त केवल 161 पेंडिंग

**झज्जर, 03 अप्रैल।** डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने समाधान शिविर की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए प्रशासन सजग है।

अभी तक समाधान शिविरों में कुल शिकायतें 5789 प्राप्त हुई हैं जिनमें

केवल 161 पेंडिंग है। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें

डीसी ने बताया कि जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में अभी तक कुल 5789 शिकायत प्राप्त हुई हैं इनमें से केवल 161 पेंडिंग हैं। पेंडिंग शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

डीसी ने जिलाभर के अधिकारियों के

साथ बैठक कर समाधान शिविरों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक शिकायत का समाधान संवेदनशीलता व गंभीरता से करें। नागरिकों की बातों को ध्यान से सुनें और उनको बताएं कि आपकी समस्या का समाधान तय समय सीमा में कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी विभागध्यक्ष

अगली बैठक में अपने विभाग से संबंधित सभी शिकायतों का अद्यतन एवं संपूर्ण डाटा साथ लेकर पहुंचें, ताकि लंबित शिकायतों को बिंदुवार समीक्षा संभव हो सके।

इस अवसर पर डीसी जगनवास, डीएफसी साहिती रेड्डी, एसडीएम बेरी रेणुका नंदल, सीटीएम ऋतु बंसीवाल, डीआरओ मनवीर सांगवान, एसीपी अनिरुद्ध चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



## उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से प्राप्त हो गैस सिलेंडर की सप्लाई : डीसी



-डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों व डीलरों के साथ की बैठक

**झज्जर, 03 अप्रैल।** डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि निर्बाध रूप से गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित करें। डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल शुक्रवार को घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों व डीलरों के साथ एलपीजी गैस, पेट्रो पदार्थों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक उपभोक्ता को ही गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वहीं संबंधित अधिकारी जिला में यह सुनिश्चित करें कि घरेलू गैस का कहीं भी कोई कर्मशियल प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है।

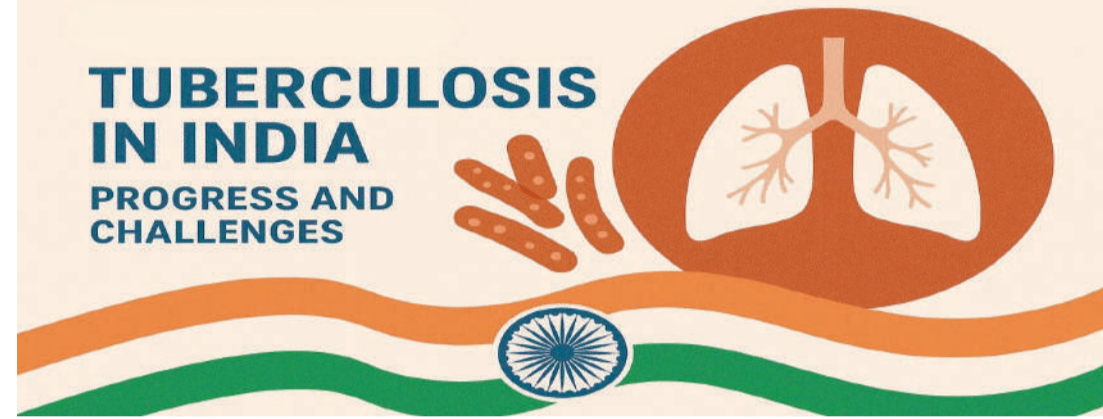
ऐसे व्यक्तियों और दुकानदारों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि जिले में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखें तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दे।

डीसी ने कहा कि जिला में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई सुचारू और सामान्य रूप से जारी है। उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। केवल एक गैस उपभोक्ता को एक ही कॉपी पर एक गैस सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है, जिसके लिए मोबाइल ओटीपी अनिवार्य है।

डीसी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति एलपीजी का अनावश्यक भंडारण करता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 पर दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की बुकिंग या वितरण से संबंधित किसी भी उपभोक्ता को यदि परेशानी आती है तो संबंधित एजेंसी द्वारा उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर डीएफओ साहिती, डीएफएससी राजेश्वर मुदगल, एएफएसओ अमरजीत सिंह, सुमित कुमार तथा जिला के सभी एजेंसी संचालक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

## टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी : सीएमओ



परिवहन विशेष न्यूज

**झज्जर, 03 अप्रैल।** सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने बताया कि जिला में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं।

सीएमओ ने बताया कि इसी कड़ी में सक्रिय केस खोज अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है

जोकि आगामी 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से प्रसिप्त मरीज शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों को शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोड़ना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम

केस खोज अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है

परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

टीबी के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निःशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।

## स्वास्थ्य जांच शिविरों में डॉक्टरों ने जांचा मरीजों का स्वास्थ्य टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अनेक गतिविधियां जारी : सीएमओ

परिवहन विशेष न्यूज

**झज्जर, 03 अप्रैल।** सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने बताया कि जिला में डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु विभिन्न गतिविधियों का प्रभावी रूप से संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निक्षय शिविरों का आयोजन, टीबी मुक्त भारत अभियान, व्यापक स्क्रीनिंग पहल, जन-जागरूकता अभियान जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां निरंतर चलाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अभियान के तहत झज्जर स्थित अनाज मंडी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-याकूपपुर, दरियापुर, पेलपा और सोधी, आर्य महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, खेड़ी जट्ट में कैप लगाकर नागरिकों के हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, एक्स-रे, बीपी आदि की जांच की गई तथा

लोगों को टीबी व अन्य रोगों के बारे में जागरूक किया गया।

यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा। यह विशेष अभियान उच्च जोखिम एवं संवेदनशील वर्गों पर केंद्रित है, जिनमें स्लम एरिया में रहने वाले लोग, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, कुपोषित व्यक्ति तथा पूर्व में टीबी से प्रसिप्त मरीज शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्क्रीनिंग के माध्यम से टीबी के संभावित रोगियों को शीघ्र पहचान करना तथा उन्हें समय पर उपचार से जोड़ना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर लक्षणों की जांच, बलगम परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने टीबी लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क



करें। टीबी का उपचार पूरी तरह निःशुल्क एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों एवं जनसहभागिता के माध्यम से ही टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता

है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें।

## स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का झज्जर दौरा आज

**झज्जर, 03 अप्रैल।** हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव शनिवार 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे नजदीकी गांव खेड़ी-खातीवास में दादा सिराज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव दोपहर 2 बजे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पार्टी मीटिंग में भाग लेते हुए कार्यक्रमों की समस्या सुनेंगी।

## वरिष्ठ नागरिकों के लिए झज्जर और बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को



**झज्जर, 03 अप्रैल।** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 07 अप्रैल को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होगा, यह शिविर बहादुरगढ़ के सेक्टर-06 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब तथा झज्जर के सेक्टर-06 में लगेगा।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, कान-नाक-गला विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर नीता देवी को बहादुरगढ़ तथा शिविर को झज्जर में आयोजित शिविर में ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे झज्जर व बहादुरगढ़ में आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं।

## जिला कारागार में महिला बंदियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर 7 अप्रैल को

**सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने दी जानकारी**

**झज्जर, 03 अप्रैल।** विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर द्वारा जिला जेल परिसर में महिला एवं वरिष्ठ नागरिक बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जेल में बंद महिला एवं बुजुर्ग कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिविल सर्जन, झज्जर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, इंटीनरी विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक तथा नेत्र विशेषज्ञ सहित अन्य आवश्यक चिकित्सक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जांच कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।

## जनसहभागिता से मजबूत होगा स्थानीय वित्तीय ढांचा : डीसी

नागरिक गूगल फॉर्म के माध्यम से दे सकेंगे अपनी राय

**झज्जर, 2 अप्रैल।** डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 27 जून 2025 की अधिसूचना के तहत सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-आई एवं 243-बाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 213 तथा हरियाणा वित्त आयोग नियम, 1994 के अंतर्गत कार्य करते हुए राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

डीसी ने बताया कि आयोग द्वारा पारदर्शी एवं सहभागी प्रक्रिया को अपनाते हुए आमजन, जनप्रतिनिधियों, संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, संगठनों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से सुझाव देने की व्यवस्था की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय सहजता से साझा कर सकें।

उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सुझाव <https://forms.gle/G5avsD16QQRdJtWLF8> लिंक के माध्यम से दिए जा सकते हैं, वहीं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव <https://forms.gle/7nhzH7TBGdbydTAn6> के लिए लिंक उपलब्ध है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गूगल फॉर्म लिंक को जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों से व्यापक और सार्थक सुझाव प्राप्त करना है, ताकि आयोग की सिफारिशें व्यावहारिक, प्रभावी एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।

डीसी ने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने सुझाव देकर स्थानीय शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में योगदान दें।

## जनगणना कार्य में सटीकता व पारदर्शिता बेहद जरूरी : डीसी

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने लघु सचिवालय में जनगणना 2027 को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की

डिजिटल मोड में होने वाली जनगणना के लिए डीसी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश



**झज्जर, 02 अप्रैल।** डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, इसलिए सभी अधिकारियों को तकनीकी पहलुओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

डीसी गुरुवार को जिला में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर वीसी उपरांत अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जनगणना-2027 को डिजिटल मोड में सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि तहसीलदार व नगर निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जनगणना कार्य से जुड़े कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी डिजिटल एप्लिकेशन तथा निर्धारित प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जनगणना से

संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आगामी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

डीसी ने कहा कि जनगणना कार्य में सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निरंतर निगरानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त करना होगा।

डीसी गुरुवार को जिला स्तर पर फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जबकि 6 से 8 अप्रैल तक उपमंडल स्तर पर जनगणना कार्य में लगे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को जनगणना-2027 की प्रक्रिया, डिजिटल डाटा संकलन प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए।

16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी सेल्फ इन्सूरेशन प्रक्रिया

आमजन 16 से 30 अप्रैल तक घर बैठे ही सेल्फ इन्सूरेशन कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। जिसके लिए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

**नागरिक सेल्फ इन्सूरेशन के लिए**  
16 भाषाओं में से अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। फॉर्म में कुल 33 सवालों के जवाब देने होंगे। नागरिकों को घर और उसकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जिसमें मेष पर अपने घर की सटीक लोकेशन मार्क करना अनिवार्य है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। फॉर्म सबमिट करने के बाद OTP के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि SE ID आपके डेटा की पहचान के रूप में काम करेगा। गणनाकर्मी घर आने पर यही SE ID दिखानी होगी।

इस अवसर पर सीटीएम ऋतु बंसीवाल, सभी सेन्सस कलर्क व जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

## रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव, आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

### संगिनी घोष

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर रायसेन में 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और खेती में बदलाव लाना है।

इस मेले का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे, जबकि समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे।

**कृषि परिवर्तन पर फोकस**  
यह महोत्सव रायसेन, विदिशा और सीहोर सहित पूरे क्षेत्र में खेती-किसानों को बदलाव की लहर लाने का माध्यम बनेगा और एक व्यापक कृषि रोडमैप तैयार करेगा।



**किसानों के लिए वन-स्टॉप समाधान**  
एक ही स्थान पर किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी।

### बीज से बाजार तक

#### दृष्टिकोण

यह मेला प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक की पूरी प्रक्रिया को जोड़ते हुए किसानों को उन्नत खेती का पूरा नक्शा प्रदान करेगा।

### तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन

मेले में ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक मशीनें और एफपीओ जैसी सुविधाओं और जानकारी को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे देखें तो यह पहल किसानों को

आधुनिक संसाधनों से जोड़कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की एक मजबूत कोशिश है।

### मुख्य बिंदु

- \* शिवराज सिंह चौहान की पहल पर कृषि महोत्सव
- \* 11 से 13 अप्रैल तक रायसेन में आयोजन
- \* उद्घाटन राजनाथ सिंह और मोहन यादव करेंगे
- \* समापन में नितिन गडकरी शामिल होंगे
- \* तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार की जानकारी एक मंच पर
- \* ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, मशीनें और एफपीओ पर जोर

### SEO Meta Description:

रायसेन में 11-13 अप्रैल को राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ी जानकारी मिलेगी।



## किडनी के अंतरराष्ट्रीय अवैध कारोबार के खिलाफ गहन जांच में जुटी कानपुर पुलिस, पांच डॉक्टरों समेत 6 गिरफ्तार

### सुनील बाजपेई

**कानपुर।** यहां किडनी के अवैध अंतरराष्ट्रीय कारोबार का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में लगातार जुटी हुई है। अब तक इस मामले में अस्पताल संचालक पांच डॉक्टरों समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार लोगों में मेरठ के डॉ. अफजल डॉ. रोहित और वैभव अनुराग की तलाश में भी छापेमारी जारी है।

जहां तक किडनी की आवाज ट्रांसप्लॉंट के खुलासे का सवाल है। इसका पर्दाफाश 50,000 रुपये के विवाद ने करा दिया।

पुलिस के अनुसार किडनी रैकेट में गिरफ्तार छह लोगों में पांच डॉक्टर शामिल हैं। इस रैकेट में कम से कम 40 लोगों, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, की अवैध सर्जरी की गई थी। आरोप है कि किडनी 10 लाख रुपये में खरीदी जाती थी और 60 लाख

रुपये में बेची जाती थी, लेकिन उनका पर्दाफाश एक छात्र के साथ हुए विवाद से हुआ, जिसने उन्हें अपनी किडनी बेची थी। यह विवाद 50,000 रुपये की मामूली रकम को लेकर था।

जानकारी के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर के एमबीए छात्र आयुष ने पुलिस को किडनी रैकेट के बारे में सूचना दी थी। मेरठ में पढ़ने वाले आयुष ने आर्थिक तंगी के चलते आरोपियों से अपनी एक किडनी 10 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनका दावा है कि उन्हें तय रकम से 50,000 रुपये कम यानी सिर्फ 9.5 लाख रुपये ही मिले।

फिलहाल सूचना मिलने के बाद जैसे ही जांच शुरू हुई और सुराग भी मिलने लगे। पुलिस को सबसे पहले शिवम अग्रवाल के बारे में पता चला, जो एक एम्बुलेंस चालक था और



आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लुभाने के लिए टेलीग्राफ जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था।

आयुष भी उसके जाल में फंस गया था। उसे 10 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर मुजफ्फरनगर की एक मरीज पारुल तोमर के परिवार से 60 लाख रुपये की उगाही की थी,

जिससे गुदों की सख्त जरूरत थी।

मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कल्याणपुर क्षेत्र के तीन अस्पतालों, जिनमें आहूजा अस्पताल, प्रिया अस्पताल और मेड लाइफ अस्पताल शामिल हैं, पर संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, मेड लाइफ अस्पताल बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया।

पुलिस ने आयुष और पारुल को अस्पताल परिसर से बरामद किया। आयुष की हालत गंभीर होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार अब तक आहूजा अस्पताल के मालिक डॉ. सुरजित सिंह आहूजा, उनकी पत्नी डॉ. प्रीति आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. राम प्रकाश, डॉ. नरेंद्र

सिंह और शिवम अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि अभी भी फरार लोगों में डॉ. अफजल, डॉ. रोहित और वैभव अनुराग की तलाश जारी है।

वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने संकेत दिया कि यह गिरोह केवल कानपुर में ही सक्रिय नहीं था, बल्कि इसके संबंध दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यहां तक कि नेपाल से भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि माना जाता है कि इस गिरोह ने विदेशियों सहित 40 से 50 अवैध प्रत्यारोपण किए थे। फिलहाल पूरे प्रकरण की गहन जांच लगातार जारी है, जिसमें और भी कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

## ईरान-इजरायल युद्ध की आंच चारधाम यात्रा तक



जयसिंह रावत

पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता युद्ध अब केवल क्षेत्रीय तनाव का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके प्रभाव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम जनजीवन तक स्पष्ट रूप से महसूस किए जा रहे हैं। इस भीषण संघर्ष की आंच सुदूर हिमालय स्थित करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुंच रही है। आगामी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली इस वर्ष की चारधाम यात्रा न केवल महंगी होने जा रही है अपितु इस संघर्ष का असर विदेशी श्रद्धालुओं के आगमन पर पड़ने की भी पूरी आशंका है। इस साल की चारधाम यात्रा के लिये गंगोत्री एवं यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को, केदारनाथ के 22 अप्रैल को तथा बदरीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। इसलिये ऋषिकेश में यात्रा का उद्घाटन 14 या 15 अप्रैल को होने की संभावना है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर वर्ष लगभग 50 लाख श्रद्धालु देश-विदेश से इन पवित्र धामों के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश पर पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का असर पहाड़ी क्षेत्रों तक भी कई गुना बढ़कर पहुंचता है। इसलिये चारधाम यात्रा की पूरी लागत संरचना प्रभावित होना स्वाभाविक है।

इस संकट का सबसे पहले असर परिवहन पर पड़ता है। इस हिमालयी तीर्थ यात्रा का अधिकांश हिस्सा सड़क मार्ग से तय किया जाता है, जहां टैक्सी, बस और निजी वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ईंधन महंगा होने से इन सेवाओं के किराए बढ़ना स्वाभाविक है। इसके साथ ही, पहाड़ों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मैदानी क्षेत्रों से होती है। जब परिवहन महंगा होता है, तो खाद्य सामग्री, होटल सेवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं भी महंगी हो जाती हैं जो सीधे श्रद्धालुओं की जेब पर बोझ डालता है। ऋषिकेश से लेकर चारों धामों तक लगभग 1300 किमी लम्बे यात्रा मार्ग हजारों की संख्या में होटल, रेस्तरां और ढाबे स्थाई और सीजनल आधार पर चलते हैं। भोजन और चाय-नास्ते के केन्द्र प्रायः एलपीजी से चलते हैं। इन दिनों सारे देश में रसोई गैस की किल्लत चल रही है जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ना स्वाभाविक है। इस किल्लत के चलते भोजन आदि की कीमतों में कम से कम 20 प्रतिशत तक उछाल आने की संभावना है, जिसका सीधा असर तीर्थ यात्रियों की जेबों पर पड़ेगा।

चारधाम यात्रा में परिवहन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली ऋषिकेश स्थित टीजीएमआय ट्रांसपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी के अनुसार अगर युद्ध के हालात नहीं सुधरे और रसोई गैस की स्थिति नहीं सुधरी तो इस साल की चारधाम यात्रा बहुत बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस बार चारधाम यात्रा के लिये 3000 हजार बसें तय की गयी हैं जिनकी बुकिंग शुरू हो गयी है। देश के विभिन्न कोनों से बसों की बुकिंग कर आने वाले तीर्थ यात्री अपना कीचन भी साथ लाते हैं और उनको यात्रा के दौरान रसोई गैस उपलब्ध करानी होती है, जो कि इस स्थिति में बहुत कठिन है। नेगी के अनुसार यात्रियों के कुछ दलों ने बसों की बुकिंग कैंसिल करा दी है।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चारधाम यात्रा केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक तंत्र है। उत्तराखंड के लाखों परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस यात्रा से जुड़ी हुई है। होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक, टूर ऑपरेटर, गाइड, थोड़ा-खूबकर मालिक, फूल-प्रसाद विक्रेता, सभी की आय का बड़ा हिस्सा इसी यात्रा से आता है। जब यात्रा महंगी होती है, तो स्वाभाविक रूप से यात्रियों की संख्या प्रभावित होती है, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग अपनी यात्रा स्थगित या सीमित कर सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

युद्ध का एक और प्रभाव अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर भी देखा जा रहा है। खाड़ी देशों और यूरोप से आने वाली उड़ानों के मार्ग में बदलाव और हवाई किराए में वृद्धि के कारण प्रवासी भारतीयों और विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। यह वर्ग आमतौर पर अधिक खर्च करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनकी अनुपस्थिति से पर्यटन क्षेत्र की आय में गिरावट आ सकती है। केदारनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी हैं लेकिन एंविपेशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण इन सेवाओं के किराए में भी बढ़ोतरी होना तय है। इसके अलावा, यदि युद्ध लंबा चलता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जिससे विमानन क्षेत्र में स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

उत्तराखंड के सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ये धाम भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव से अछूते नहीं हैं। यह परस्पर जुड़ाव आधुनिक विश्व की एक सच्चाई है, जहां एक क्षेत्र में युद्ध का प्रभाव हर जुड़ाव किलोमीटर दूर बैठे लोगों के जीवन पर पड़ता है। इस स्थिति में स्थानीय स्तर पर भी नवाचार की आवश्यकता है। पर्यटन से जुड़े लोगों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और विविधता बढ़ानी होगी, ताकि कम संख्या में आने वाले यात्रियों से भी बेहतर आय प्राप्त की जा सके। स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित किए जा सकते हैं।

चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसे वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी सुचारु और सुरक्षित बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे, ताकि आस्था की यह यात्रा आर्थिक संकट का शिकार न बने। ईरान-युद्ध की आंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज का विश्व कितना परस्पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि हम न केवल तात्कालिक चुनौतियों का सामना करें बल्कि दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण धार्मिक और आर्थिक तंत्रों को मजबूत बनाएं। चारधाम यात्रा की निरंतरता और उसकी गरिमा को बनाए रखना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

## पक्षियों की आवाज़ें न केवल हमें आनंद देती हैं, बल्कि व हमें प्रकृति की सुंदरता का भी अनुभव कराती हैं

हमें पक्षियों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वे हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षियों की जरूरतों का ध्यान रखने से हम न केवल उनकी मदद कर सकते हैं, बल्कि हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।

हम पक्षियों के लिए पानी के स्रोत बना सकते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, और उनके लिए आश्रय बना सकते हैं। इन छोटे-छोटे कदमों से हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को भी स्वस्थ बना सकते हैं।

गर्मियों का आहट शुरू हो गई है। हमें अपने आसपास के पक्षियों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ये बड़े मासूम होते हैं। गर्मियों में पक्षियों को पानी की सबसे

ज्यादा जरूरत होती है। हम अपने घरों के बाहर पानी के बर्तन रख सकते हैं जिसमें पक्षी पानी पी सके।

पक्षियों को दाना डाल देना भी एक अच्छा विचार है। हम अपने घरों के बाहर दाना डालने के लिए एक जगह बना सकते हैं जहां पक्षी आकर दाना खा सके।

गर्मियों में पक्षियों को छांव की भी जरूरत होती है। हम अपने घरों के बाहर लगे पेड़ों पर व्यवस्थाएं बना सकते हैं, या छांव के लिए एक छतरी बना सकते हैं जहां पक्षी आकर आराम कर सके।

इन सुझावों को अपनाकर, हम पक्षियों की मदद कर सकते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल! पक्षियों का कलरव वास्तव में मनमोहक होता है। उनकी मधुर आवाजें और चहचहाहट हमें प्रकृति के करीब ले जाती हैं और हमारे मन को शांति



और सुकून से भर देती है। पक्षियों की आवाजें न केवल हमें आनंद देती हैं, बल्कि वे हमें प्रकृति की सुंदरता और

विविधता का भी अनुभव कराती हैं। जब हम पक्षियों की आवाजें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम प्रकृति के बीच में हैं, और यह अनुभव

हमें बहुत आनंद और शांति देता है। डॉ. मुरगताक अहमद शाह सहज हरदा मध्य प्रदेश,

## अलोकतांत्रिक और अन्याय पूर्वक है साहित्य अकादमी की कार्यशैली

### डा. विनोद बब्बर

साहित्य अकादमी के गठन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के संवर्धन हेतु किया था लेकिन इसकी जटिल रचना, विचित्र चुनाव प्रक्रिया ने साहित्य अकादमी को ऐसे लोगों का जमावड़ा बना दिया जो साहित्य की बजाय भारतीय संस्कृति विरोधी विचार को देखकर निर्णय करने लगे। यह यक्ष प्रश्न है कि दुनिया के इतिहास में क्या कोई ऐसी दूसरी संस्था है जहाँ अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य ही नए सदस्यों का चयन करते हैं। क्या यह कोई राजशाही है जहाँ राजा अपना उत्तराधिकारी स्वयं तय करें? जिस संस्था की रचना इतनी जटिल है, उसकी कार्यशैली भी अव्यवहारिक है। सुनने में यह है अच्छा लग सकता है कि साहित्य अकादमी सभी भारतीय भाषाओं के साथ समान व्यवहार करती है। प्रत्येक भाषा को एक सम्मान की बात सुनकर ताली बजाने वाले लोग समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते कि डोगरी और बोडो बोलने वाली कुल जनसंख्या से भी अधिक हिंदी के लेखक हैं। अतः एक समान व्यवहार का जुनूना उचित नहीं है। कुछ भाषाओं में पुरस्कार प्राप्त गली-गली हो और देश के लगभग सभी राज्यों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई

जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों को ढूँढना पड़ता है।

वह साहित्य अकादमी ही है जिसने देश की संविधान की आठवीं अनुसूची भाषाओं के अतिरिक्त कुछ बोलियों को अलग से सम्मान देने की परंपरा शुरू की। उसी का परिणाम है कि हिंदी को सम्भूद्ध करने वाली बोलियों के मन में अलगाव के विचार पनपा। आज अनेक बोलियों के लोग संविधान में अलग दर्जा मांग रहे हैं तो उस पाप के लिए साहित्य अकादमी की कार्यशैली जिम्मेदार है।

छोटी-छोटी बोलियों और लगभग 100 करोड़ के लोगों की भाषा हिंदी को समकक्ष रखने का विचार भाषा और संस्कृति के विखंडन को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है। इसलिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी को लोकतांत्रिक बनाया जाए। साहित्य अकादमी को लोकतांत्रिक और निष्पक्ष बनाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि उसकी प्रक्रिया पारदर्शी हो।

यह अब कोई छुपा रहस्य नहीं है कि साहित्य अकादमी पर लंबे समय से काबिज कांग्रेस-सामिपति गिरोह ने मनमाने ढंग से चयन-समिति का गठन और निर्णय की परंपरा आरंभ की। इस बार भी हिंदी पुरस्कार तय करने का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया उनका एक विचारधारा विशेष में



विश्वास तो अवश्य है लेकिन हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, यह बताने योग्य उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे में साहित्य अकादमी के पुरस्कार 'अंधा बॉटे रेवड़ी' की तर्ज पर बॉटे गए।

हमने साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी की उपेक्षा का प्रश्न बार-बार उठाया है। साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय को भी पत्र लिखे लेकिन पत्र का उत्तर तो दूर, पावती की तय करने का जिम्मा जिन लोगों को दिया गया उनका एक विचारधारा विशेष में

बदला जाए। हिंदी के लिए हर विधा में अलग पुरस्कार दिया जाए ताकि एक विचारधारा विशेष द्वारा किए गए अन्याय को दूर किया जा सके।

जो लोग साहित्य अकादमी को स्वायत्त संस्था बताते हैं, वे यह भूलते हैं कि केंद्रीय साहित्य अकादमी की सभी गतिविधियां केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सैकड़ों करोड़ रुपये के अनुदान से चलती हैं। क्या अनुदान देने वाले को संस्था की गड़बड़ियों के प्रति आंखें मूंद रखना चाहिए?

भारत लोकतांत्रिक देश है जहां बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबंधन शासन चलाते हैं तो बहुमत की भाषा की अपेक्षा को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? सरकार को तत्काल प्रभाव से समिति का गठन करना चाहिए जो साहित्य अकादमी की कार्यशैली से चुनाव प्रक्रिया तक की समीक्षा करत हुए सुधार के सुझाव दे।

डा. विनोद बब्बर अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती (अखिल भारतीय साहित्य परिषद)

# सुनहरे गेहूँ की कहानी: प्राचीन रीति-रिवाजों से लेकर मशीन युग तक का एक बड़ा परिवर्तन



डॉ. विजय गर्ग



प्राचीन काल में गेहूँ की खेती पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से होती थी। बीज बोने से लेकर कटाई तक हर काम हाथ से किया जाता था। हल से जमीन उगाई जाती थी, बीज छिड़के जाते थे और पानी देने के लिए नहरों या कुओं का सहारा लिया जाता था। कटाई के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अनाज काटते थे। यह समय न केवल परिश्रम का होता था, बल्कि खुशी और मेलजोल का भी होता था।

गेहूँ पंजाब की धरती का वैभव है। जब खेतों में सुनहरी बालें हवा के झोंके से लहराती हैं, तो यह दृश्य किसान के साल भर के परिश्रम का प्रतीक बन जाता है। गेहूँ सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवन शैली से जुड़ी कहानी है।

प्राचीन काल में गेहूँ की खेती पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से होती थी। बीज बोने से लेकर कटाई तक हर काम हाथ से किया जाता था। हल से जमीन उगाई जाती थी, बीज छिड़के जाते थे और पानी देने के लिए नहरों या कुओं का सहारा लिया जाता था। कटाई के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अनाज काटते थे। यह समय न केवल परिश्रम का होता था, बल्कि खुशी और मेलजोल का भी होता था।

पंजाब की धरती और गेहूँ का रिश्ता सदियों पुराना है। जिसे हम आज 'सोना' कहते हैं, उसने पिछले कुछ दशकों में एक लंबी और दिलचस्प यात्रा की है। हल के दस्तों से लेकर कबाड़ियों की आवाज तक, गेहूँ की कहानी मानव परिश्रम और वैज्ञानिक प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है।

पुराना दौर: परिश्रम और साझेदारी का प्रतीक प्राचीन काल में गेहूँ की खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक उत्सव के समान थी। उस समय के प्रमुख पहलू थे: बैलों की जोड़ी: खेतों की सफाई लकड़ी के हलकों और बैलों की मदद से की जाती थी। किसान सुबह-सुबह अंधेरे में ही खेतों की ओर निकल जाते थे। हाथ से बोना: बीजों को हाथ से काटकर या 'पोरे' के माध्यम से बोया जाता था। दाती की गड़गड़ाहट: कटाई के दिनों में पूरा गांव एक-दूसरे की मदद करता था। दानी के साथ लंबी लाइनों में खड़े होकर गेहूँ काटना होता था और 'भरी' बांधली जाती थीं। फल और पिंड: गेहूँ को निकालने के लिए बैलों के पीछे से दाल बांधकर काट दिया जाता था, फिर हवा के रुख के अनुसार अनाज को अलग कर दिया जाता था।

हरित क्रांति: एक बड़ा मोड़ 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। मैक्सिकन प्रजातियों के आगमन से झाड़ियों में भारी वृद्धि हुई। इंधन की कमी और वैज्ञानिक प्रगति का एक अद्भुत उदाहरण है।

को जाता है।

मशीन युग: गति और सुविधा आज के समय में कृषि का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है: ट्रैक्टर और सुपर सीडर: अब सप्ताहों का काम घंटों में हो जाता है। सुपर सीडर जैसी मशीनों से बिना जलाए परली को उगाना संभव हो गया है। कंबाइन हार्वेस्टर: जहां पहले कटाई और गहाने में महीनों का समय लगता था, अब कंबाइन कुछ ही मिनटों में खेत साफ कर देता है। ड्रोन और तकनीक: अब ड्रोन के माध्यम से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने की तकनीक भी फैल रही है।

गेहूँ की कटाई भी एक अलग प्रक्रिया थी। बिल्लियों को इकट्ठा करके बैलों से रोया जाता था, ताकि दाने अलग हो जाएं। इसके बाद हवा में फेंका गया भूसा और दाने अलग कर दिए जाते थे। इन सभी कार्यों में बहुत समय लगता था, लेकिन इसमें साझाकरण और सहयोग की भावना भी होती थी।

मशीनरी युग के आगमन से गेहूँ की खेती में बड़े बदलाव आए हैं। अब खेतों को ट्रैक्टरों से जोड़ा जाता है, बीज ड्रिल से बोए जाते हैं और कटाई और कटाई एक ही समय में होती है। इससे समय और

श्रम दोनों की बचत होती है तथा उत्पादन भी बढ़ जाता है।

लेकिन इस प्रगति के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। मशीनों के उपयोग से खर्च बढ़ गया है और छोटे किसानों के लिए ये मशीनों खरीदना आसान नहीं है। इसके अलावा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उपज और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा है।

आज हमें पुरानी प्रथाओं और नई प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहां मशीनों से सुविधा और उत्पादन बढ़ता है, वहां हमें प्रोगेमिक तरीकों और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी महत्व देना चाहिए।

अंततः, सुनहरे गेहूँ की यह कहानी हमें बताती है कि समय के साथ बदलाव आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यही संतुलन हमें भविष्य में एक स्थिर और समृद्ध कृषि प्रणाली की ओर ले जा सकता है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब



संपादकीय

चिंतन-मगन



## सुधार या बोझ? आम आदमी की जेब पर लगातार पड़ता वार

देश में कई फैसले ऐसे होते हैं, जो कागज पर छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका असर सीधे रसोई, सड़क और जेब तक पहुंचता है। 11 अप्रैल 2026 भी ऐसी ही तारीख बन गई। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आम आदमी पर तीन तरफ से बोझ डाला गया—नया इनकम टैक्स कानून, ई20 पेट्रोल का अनिवार्य उपयोग और फारस्टैग का महंगा वार्षिक पास।

सरकार इन बदलावों को सुधार कह रही है, लेकिन असली असर वही मध्यम वर्ग झेल रहा है, जो पहले से महंगाई, किस्तों और रोजमर्रा के खर्चों में फंसा हुआ था। यह सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं, बल्कि आम आदमी की आय स्थिर रहकर खर्चों के बढ़ते दबाव का नया दौर है।

सबसे बड़ा बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूप में आया है। छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान, पारदर्शी और आधुनिक बनेगा। कागजों पर राहत भी दिखती है। बच्चों का शिक्षा भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह, हॉस्टल भत्ता 300 से 9000 रुपये और भोजन भत्ता व गिफ्ट लिमिट भी कई गुना बढ़ाई गई है। पहली नजर में यह राहत का पैकेज लगता है, लेकिन असलियत अलग है। इन बड़ी हुई सीमाओं के साथ शर्तें और कागजी बोझ भी बढ़ गया है। नतीजा यह कि कीमत भले न बढ़े, वास्तविक खर्च बढ़ जाएगा।

माइलेज घटने से महीने के अंत तक कड़ सी रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। रोज भरत जाने वाले कर्मचारी, टैक्सि चालक, डिलीवरी कर्मी और छोटे व्यापारी सबसे पहले प्रभावित होंगे। सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह नया खर्च बड़ी समस्या बन सकता है। सरकार को नई फैसला लागू कर दिया, लेकिन पुराने वाहनों वाले लाखों परिवारों की तैयारी नहीं हुई।

सड़क पर निकलने वालों के लिए सबसे तात्कालिक झटका फारस्टैग के

नए नियमों ने दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फारस्टैग के वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी है। सुनने में यह केवल 75 रुपये की बढ़ती लगती है, लेकिन असली बोझ इससे कहीं बड़ा है। अब 'वन व्हीकल, वन फारस्टैग' नियम पहले से सख्ती से लागू है और नेटवर्क पर ज्यादा निर्भर हो गया है। यानी अब सड़क पर निकलने से पहले गाड़ी नहीं, फारस्टैग का सक्रिय होना ज्यादा जरूरी हो गया है।

इन तीनों बदलावों की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग पर पड़ेगी। सीमित आय वाले एक सामान्य परिवार की जेब पर अब हर महीने 800 से 1200 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नए टैक्स नियम बचत बढ़ाएंगे, ई20 पेट्रोल रोज की यात्रा महंगी करेगा और फारस्टैग हर सप्ताह को ज्यादा खर्चीला बना देगा। यही वह वर्ग है, जो पहले ही बच्चों की फीस, राशन, बिजली बिल और ईएमआई के बीच जूझ रहा है। न उसे सरकारी राहत मिलती है, न बढ़ती महंगाई से बचने का रास्ता। इसलिए सरकार जिन कदमों को सुधार कह रही है, वे आम आदमी की जेब पर लगातार पड़ते वार जैसे लग रहे हैं।

किसी भी सुधार का मूल्य उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से तय होता है। टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, तेल पर निर्भरता घटाना और टोल को डिजिटल करना जरूरी हो सकता है, लेकिन बिना तैयारी और विकल्प के लागू किए गए बदलाव सुधार नहीं, बोझ बन जाते हैं। 1 अप्रैल 2026 ने यही सच्चाई सामने रखी। इस दिन देश ने कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि यह महसूस किया कि आने वाले समय में आम आदमी को अपनी कमाई से ज्यादा अपने बढ़ते खर्चों की चिंता करनी होगी।

सड़क पर निकलने वालों के लिए सबसे तात्कालिक झटका फारस्टैग के

## डिजिटल बाल यौन शोषण — ऑनलाइन युग में एक बढ़ता संकट

डॉ. विजय गर्ग

डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने लोगों के जुड़ने, सीखने और संवाद करने के तरीके को बदल दिया है। हालांकि, इन लाभों के साथ-साथ एक अंधकारमय वास्तविकता भी उभर आई है। डिजिटल बाल यौन शोषण एक गंभीर और बढ़ती वैश्विक चिंता है जो बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य को खतरा बनाती है। डिजिटल बाल यौन शोषण क्या है?

डिजिटल बाल यौन शोषण से तात्पर्य बच्चों का यौन शोषण करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल उपकरणों या डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग है। इसमें संवारना, अपमानजनक छवियों को साझा करना या बनाना, दबाव डालना और लाइव-स्ट्रीम दुर्व्यवहार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। दुर्व्यवहार के पारंपरिक रूपों के विपरीत, यह शोषण अक्सर शारीरिक संपर्क के बिना होता है, जिससे इसका पता लगाना और रोकथाम करना कठिन हो जाता है। अपराधी गुमनाम रूप से और सीमा पार करके काम कर सकते हैं, जिससे समस्या से निपटने की जटिलता बढ़ जाती है।

ऑनलाइन शोषण के रूप डिजिटल शोषण कई रूप ले सकता है, जिनमें शामिल हैं ऑनलाइन संवारना: किसी बच्चे के साथ यौन शोषण या हेरफेर करने के लिए उसका विश्वास बढ़ाना बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएम): स्पष्ट छवियों या वीडियो का निर्माण और वितरण यौन उन्पीड़न: अंतरंग चित्रों या धमकियों का उपयोग करके बच्चों को ब्लैकमेल करना लाइव स्ट्रीमिंग दुरुपयोग: इंटरनेट पर वास्तविक समय शोषण प्रसारण स्व-जनित सामग्री का दुरुपयोग: बिना सहमति के साधियों द्वारा निजी छवियों को साझा करना इन गतिविधियों में अक्सर जबरदस्ती, धोखा या सत्ता का दुरुपयोग शामिल होता है, जहां बच्चा सूचित



सहमति देने में असमर्थ हो जाता है।

समस्या क्यों बढ़ रही है? डिजिटल बाल शोषण के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया है। 1. व्यापक इंटरनेट पहुंच: बच्चे पहले से कहीं अधिक कम उम्र में ऑनलाइन होते हैं। 2. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: दुनिया भर में अजनबियों के साथ आसान संवाद। 3. अपराधियों की गुमनामी: छिपी हुई पहचान ट्रैकिंग को कठिन बना देती है। 4. तकनीकी प्रगति: एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उपकरण

हाल की रिपोर्टें चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती हैं। हर साल लाखों मामले दर्ज किए जाते हैं, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया भर में करोड़ों बच्चे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में ऑनलाइन यौन शोषण का अनुभव करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि एआई-जनित अपमानजनक सामग्री बढ़ रही है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका पता लगाना कठिन हो रहा है।

बच्चों पर प्रभाव डिजिटल यौन शोषण के परिणाम गंभीर और दीर्घकालिक हैं: भावनात्मक आघात, चिंता और अवसाद विश्वास और आत्मसम्मान का नुकसान

सामाजिक अलगाव और भय दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक नुकसान भले ही दुर्व्यवहार ऑनलाइन हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत वास्तविक है, क्योंकि डिजिटल सामग्री को बार-बार साझा किया जा सकता है, जिससे पीड़ित का कष्ट बढ़ जाता है।

मुद्दे को सुलझाने में चुनौतियां डिजिटल बाल शोषण से लड़ने में अचूकी चुनौतियां हैं कम रिपोर्टिंग: कई पीड़ित अपनी बात कहने में शर्म या डर महसूस करते हैं। सीमा पार अपराध: अपराधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी: कानून प्रवर्तकों को तालमेल बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी: माता-पिता और बच्चे जोखिम को नहीं पहचान पाते। अध्यायनों से यह भी पता चलता है कि कई पीड़ित कभी अपने दुर्व्यवहार करने वालों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते, फिर भी नुकसान बहुत गहरा होता है और कभी-कभी ऑफलाइन दुर्व्यवहार में बदल जाता है।

रोकथाम और संरक्षण इस संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है डिजिटल शिक्षा: बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाना माता-पिता की जागरूकता: निगरानी और खुला संचार

मजबूत कानून और प्रवर्तन: अपराधियों को वैश्विक स्तर पर निशाना बनाना टेक कंपनियों की जिम्मेदारी: हानिकारक सामग्री का पता लगाना और हटाना रिपोर्टिंग तंत्र: पीड़ितों और गवाहों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष डिजिटल बाल यौन शोषण आधुनिक डिजिटल युग के सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे प्रयास भी विकसित होने चाहिए। जागरूकता, शिक्षा और समन्वित वैश्विक कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इंटरनेट अवसर का स्थान बना रहे। समाज के सबसे युवा और सबसे कमजोर सदस्यों के लिए नुकसान नहीं होगा। समस्या के पैमाने को स्वीकार करके और एक साथ काम करके ही हम एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाशास्त्री स्ट्रीट कोर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

## सीबीआई की सीमाएं और सवाल (जब जांच एजेंसी बन जाए राजनीति का केंद्र बिंदु)

डॉ. प्रियंका सोरभ

भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का राज्य क्षेत्राधिकार एक ऐसा संवेदनशील और बहुपरतीय मुद्दा बन चुका है, जो केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह विभिन्न राज्यों—विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों—ने सीबीआई को दोषी सामान्य सहमति (जनरल कंसेंट) वापस ली है, उसने इस बहस को और अधिक तीखा बना दिया है। यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि क्या सीबीआई वास्तव में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है या फिर वह केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करने वाली संस्था बनती जा रही है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह दावा है कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जांच एजेंसियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सच इन दोनों अंतियों के बीच कहीं स्थित है।

सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीए अधिनियम) को समझना आवश्यक है। यही वह कानून है जो सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी राज्य में सीबीआई को अपनी शक्तियों का अधिकार होना चाहिए। 12018 के बाद से पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने सीबीआई को दोषी सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसका अर्थ होता है कि सीबीआई राज्य में बिना हर बार अनुमति लिए जांच शुरू कर सकती है। इसकी वापसी के बाद सीबीआई को हर मामले में अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है।

राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के मामलों में डिलेरी बरती जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में सामान्य सहमति वापस लेते समय इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का कदम बताया। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें सहमति रोककर भ्रष्टाचार और अपराध की जांच में बाधा डाल रही हैं। यदि हर मामले में राजनीतिक अनुमति की आवश्यकता होगी, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी।

खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे राष्ट्रीय हित तथा न्यायिक प्रक्रिया के सामने झुकना पड़ सकता है।

भारतीय संविधान का संघीय ढांचा भी इस पूरे विवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को एक सहकारी संघवादी देश का उदाहरण माना जाता है, लेकिन यह पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं है। सातवीं अनुसूची में कानून-व्यवस्था को राज्य सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में यह राज्यों का विषय है। लेकिन अनुच्छेद 246 और 254 के तहत केंद्र को विशेष परिस्थितियों में प्रधानता प्राप्त है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जांच एजेंसियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सच इन दोनों अंतियों के बीच कहीं स्थित है।

यही से यह टकराव उत्पन्न होता है। एक ओर राज्य अपनी संवैधानिक स्वायत्तता का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र यह तर्क देता है कि राष्ट्रीय हित और व्यापक न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। 12018 के बाद से पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने सीबीआई को दोषी सामान्य सहमति वापस ले ली है। इसका अर्थ होता है कि सीबीआई राज्य में बिना हर बार अनुमति लिए जांच शुरू कर सकती है। इसकी वापसी के बाद सीबीआई को हर मामले में अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है।

राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के मामलों में डिलेरी बरती जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में सामान्य सहमति वापस लेते समय इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का कदम बताया। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें सहमति रोककर भ्रष्टाचार और अपराध की जांच में बाधा डाल रही हैं। यदि हर मामले में राजनीतिक अनुमति की आवश्यकता होगी, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2021 में इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से अंतरराज्यीय और जटिल अपराधों की जांच प्रभावित होती है। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक हितों के संदर्भ में देख रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इससे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जब किसी जांच एजेंसी पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सीबीआई को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं देखा जाएगा, तो उसके द्वारा की गई जांच और कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ जाएगी।

इसके साथ ही, राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति भी एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि हर राज्य अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों को प्रवेश से रोकने लगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपराधनिष्पक्ष और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे अपराध जो कई राज्यों में फैले होते हैं, उनकी जांच के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता होती है।

समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग में निहित है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि सीबीआई की स्वायत्तता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष की भी भागीदारी हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीबीआई किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे।

दूसरे, डीएसपीए अधिनियम में संशोधन कर एक स्पष्ट और संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकारें सहमति देने या न देने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लें। यदि निर्धारित समय भी नहीं निर्णय नहीं लिया जाता, तो उसे स्वीकृत माना जाए। इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है।



# 2027 के चुनावों में मान सरकार के पक्ष में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 सीटों पर जीत दिलाने के लिए मतदाता अभी से तैयार – धालीवाल

\* संघर्ष करके 15 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी डिग्री व व्यावसायिक कॉलेज सहित करोड़ों के विकास कार्य पूरे किए गए – धालीवाल

\* खराब मौसम के बावजूद 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' संवाद कार्यक्रमों में महिलाओं सहित ग्रामीणों की भारी भागीदारी

अमृतसर/अजनाला, 3 अप्रैल (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज खराब मौसम के बावजूद गांव डबबर बस्ती, तलवंडी राय दादू, छोटा फतेवा, चक्क डोगरा, वंजावाला, नंगल, सराय, रियाड़ और उगर ओलख में आयोजित 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' संवाद कार्यक्रमों में महिलाओं सहित आम ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भारी भागीदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों को पिछले 8 दिनों में दर्जनों गांवों में हुए आयोजनों में भी लोगों ने स्वतः उत्साह के साथ भाग लेकर जो प्यार और सम्मान दिया है, उससे वे और अधिक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिकराऊर में 15 करोड़ रुपये की लागत से नया सरकारी डिग्री व व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करने, रावी नदी के धुस्सी बांध घेनेवाला से गुलगढ़ तक 60 करोड़



रुपये की लागत से नई सड़क बनाने के अलावा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के अन्य बहुआयामी विकास कार्यों को पूरा करने, रोजगार, कानून-व्यवस्था की मजबूती, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संकल्पित हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 70 वर्षों तक पंजाब की सत्ता में रही पारंपरिक पार्टियों ने सीमावर्ती क्षेत्र अजनाला को विकास और रोजगार के मामले में पूरी तरह नजरअंदाज कर इसके माथे पर पिछड़ेपन का दाग लगाया।

सरदार धालीवाल ने लोगों से मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में लोगों ने पारंपरिक पार्टियों की पूर्व सरकारों द्वारा कथित लूट,



डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, गैंगस्टरवाद जैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मान सरकार को चुना था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 वर्षों में

अपनी चुनावी गारंटियों को 100 प्रतिशत लागू कर जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए लोगों का भरोसा जीता है और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए पंजाब के मतदाता 2027 के चुनावों में पिछली 92 सीटों के मुकाबले 100 विधानसभा सीटों पर मान सरकार को जीत दिलाने के लिए अभी से तैयार हैं। इसका प्रमाण यह है कि अजनाला सहित राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' कार्यक्रमों को लोगों का स्वतः उत्साह मिल रहा है।

इस मौके पर खुशपाल सिंह धालीवाल, पीए मुख्तार सिंह बलडवाल, गुरजेंट सिंह सोही, शहरी प्रधान व चेयरमैन अमित औल, एडवोकेट संदीप कौशल गट्टू, ब्लॉक प्रधान सरबजीत सिंह, हरमनजीत सिंह नंगल आदि के अलावा बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और स्वयंसेवक मौजूद थे।

## डॉ. एस. एन. मोदानी को ग्लोबल टेक्सटाइल लीडरशिप लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड



!!ATEXCON 2026 में सम्मानित, वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग में योगदान को मिली बड़ी पहचान!!

अनूप कुमार शर्मा परिवहन विशेष

भीलवाड़ा डॉ. एस. एन. मोदानी, चेयरमैन, RTMA (राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन) एवं वाइस चेयरमैन, संगम ग्रुप, भीलवाड़ा को ग्लोबल टेक्सटाइल लीडरशिप लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2026 विधानसभा क्षेत्रों में 'शानदार चार साल भगवंत मान के साथ' कार्यक्रमों को लोगों का स्वतः उत्साह मिल रहा है।

एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस (ATEXCON 2026) के दौरान प्रदान किया गया (यह सम्मान समारोह 2 अप्रैल 2026 को होटल नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित हुआ, जिसमें तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनुमोला रेवंत रेड्डी की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह सम्मान डॉ. मोदानी को श्री तुम्मला नागेश्वर राव (हैडलूमस एवं टेक्सटाइल मंत्री, तेलंगाना) एवं श्री डी. श्रीधर बाबू (आईटी, इंडस्ट्री एवं कॉमर्स से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान कम्पेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) द्वारा 13 वें

को यह सम्मान टेक्सटाइल उद्योग के विकास, नवाचार एवं परिवर्तन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, अग्रणी योगदान एवं आजीवन समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है।

इस उपलब्धि पर देश-विदेश के टेक्सटाइल जगत से जुड़े उद्योगपतियों, विशेषज्ञों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉ. मोदानी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सम्मेलन के दौरान डॉ. मोदानी ने पैनल चर्चा में भी भाग लिया और अपने विचार साझा किए।

## स्कूलों के वाहन संचालन में नहीं चल पाएगी मनमानी



परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। जनपद में इस समय

स्कूली वाहन फिटनेस अभियान चल रहा है जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत पोर्टल के माध्यम से स्कूली बसों की सारी जानकारी इकट्ठा करके आईएसबीएम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से बसों की सारी जानकारी एक ही जगह से प्राप्त की जा सकेगी। इसे परिवहन विभाग ने विकसित किया है। इससे स्कूल वाहनों के संचालन में कोई मनमानी नहीं की

जा सकेगी। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा। यही नहीं स्कूल की मान्यता तक भी रद्द की जा सकती है।

प्रदेश सरकार ने बच्चों की सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 01 से 15 अप्रैल तक विशेष स्कूली वाहन फिटनेस अभियान शुरू किया है। इसके दौरान वाहनों का पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, बीमा और भौतिक स्थिति की जांच की जा रही है। इन स्कूली वाहनों में किसी भी प्रकार की

खामियां मिलने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जानकारों की माने तो खराब, गलत फिटनेस वाले वाहन दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं जिसे खत्म करने के लिए यह किया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने शासन के निर्देश पर यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया है जो पहली अप्रैल से लाइव हो गया है। पोर्टल के नो योर बस फीचर के जरिए स्कूली वाहनों की पूरी जानकारी विवरण सभी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

## सरायकेला जिले का स्थापना दिवस तिथी बदलने से भड़के पूर्व विधायक अनंत

पुछा किस सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक ऐतिहासिक जिले की स्थापना तारीख बदलने में ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना दिवस कल यानी 4 अप्रैल को मनाया जायेगा यद्यपि गत वर्ष तक इसकी स्थापना दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता रहा।

अपने विधायकी कार्यकाल में जिला बना सरायकेला का तिथी बदलने पर सरायकेला के पूर्व विधायक अनंत राम टूडू ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने जानना चाहा है कि सरकार के किस नोटिफिकेशन के तहत एक ऐसा जिला का स्थापना दिवस तिथी को ही दिया बदल दिया जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज केंद्र से लेकर और दो अन्य राज्यों के पास भी सुरक्षित है। जहां आज जमीन, राजस्व, न्याय समेत हर जगह जिला में भ्रष्टाचार राज कर रहा है ऐसा मानना है झारखंड गठन के साथ मंत्री नहीं बनाये जाने पर लोक लेखा समिति अध्यक्ष का पद में बैठाए गये इस विधायक का। उन्होंने इस पर उच्चस्तरीय जांच व कारवाई की मांग करने पर बल दिया है।

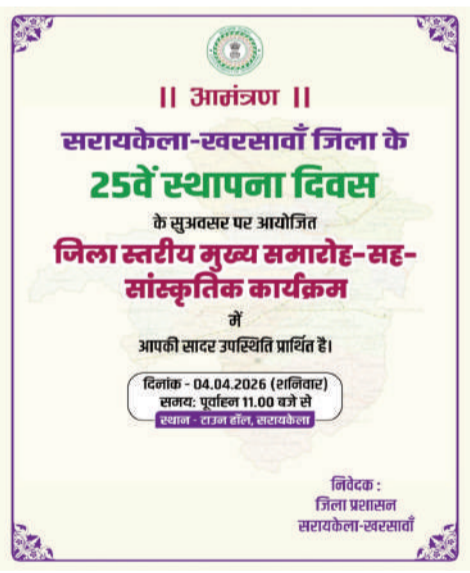
सरायकेला के इमानदार पूर्व विधायक अनंत राम टूडू जो सरायकेला खरसावां जिला उद्घाटन के समय विधायक थे उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले का स्थापना तिथी बदलने पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है 15 नवम्बर 2000 में झारखंड बनने के बाद सरायकेला खरसावां को उनके विधायकी कार्यकाल में 2021 में 30 अप्रैल को जिला बनाया



गया। तब वे बाबूलाल मरांडी तत्कालीन कमिश्नर शिला राजप किस्कू के साथ बंदना डाडेल को इसकी प्रशासनिक बागडोर संभालने हेतु दिया गया था, जो पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त राजीव अरुण एक्का के समय पृथक हुआ था। तब इसका विधिवत उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हवाई मार्ग से आकर आज के अनुमंडल कार्यालय के उस ऐतिहासिक भवन में 30 अप्रैल 2001 सोमवार को की थी जिस भवन कभी सरायकेला प्रिन्सली स्टेट का ऐतिहासिक सेक्रेटरीएट रहा। जिस प्रिन्सली स्टेट का विधिवत विलय सरदार पटेल के हाथों हुआ था।

पूर्व विधायक ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि किस व्यक्ति के इशारे

पर सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना तारीख में बदलाव किया गया है। उन्होंने जानना चाहा कौन से नोटिफिकेशन के तहत ऐसा हुआ है ? यद्यपि सरायकेला खरसावां जिला गठन के बाद से अनेक सरकारी दस्तावेज इधर से उधर किये गये जिसे लोग खूब जानते हैं। विशेषकर जमीन का बड़ा खेल हुआ जो आज भी धड़ल्ले से जारी है हर अंचल में। झारखंड गठन के बाद प्रथम लोकलेखा समिति के अध्यक्ष रहे इस विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षित विधायक टूडू की मानें तो इससे बड़ी गड़बड़ी एवं सरायकेला का समृद्ध इतिहास को खत्म करने का चाल भी है। उन्होंने कहा है इस पर वे आगे आवाज उठाकर कार्रवाई करवायेंगे। लोगों की तथा सरकारी जमीन, राजस्व, विकास, न्याय के जगह अन्याय परोसे जाने का उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। कारण आम आदमी भी इससे नाखुश है।

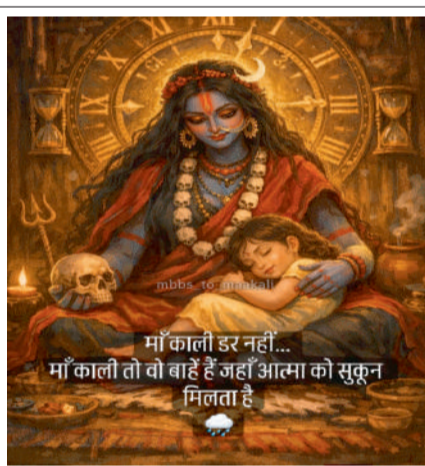


## छपास की ऐसी भी क्या बीमारी:....?

छपास कोई चिकित्सीय बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति या व्यवहारिक लक्षण है, जिसे सस्ती लोकप्रियता पाने की भूख कहा जाता है।

सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति हर बात पर अखबारों में छपने या सुर्खियों में बने रहने के लिए बचैन रहता है, तो उसे छपास रोग से पीड़ित कहा जाता है!!

भूषेण सारस्वत 'सारथी' बरेली (उ०प्र०).



जब दुनिया टुकरती है, जब मन टूटकर बिखर जाता है, जब अपने भी समझ नहीं पाते हैं तब माँ काली चुपचाप अपने आँचल में जगह दे देती हैं।

वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं, वो टूटे हुए मन की मरहम भी हैं, उर के अधरे में जलती हुई दीपशिखा भी हैं, और भटकी हुई आत्मा का घर भी।

माँ काली का रूप भले प्रचंड है, पर उनका हृदय सबसे कोमल है। जो उनके पास आ गया है वो फिर कभी अकेला नहीं रहा।

## क्यों हो रहा है कैंसर, इस पर शोध की जरूरत — लोकसभा में रखी है मांग : शैलजा

अंडरपास के लिए रेल मंत्री के समक्ष रखी है मांग, सरकार ले जल्द फैसला : शैलजा

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा) : सिरसा से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा उकलाना में गुलशन भंगू के पिता लखविंदर सिंह भंगू के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होना अच्छे संकेत नहीं है। इसके लिए सरकार को व्यापक स्तर पर शोध करने की जरूरत है कि आखिर कैंसर क्यों बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इलाज के लिए अस्पतालों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन यह भी जरूरी है कि बीमारी के मूल कारणों का पता लगाया जाए। आज नहरों और जमीन का पानी क्यों खराब हो रहा है,

क्या उसमें किसी प्रकार के केमिकल मौजूद हैं या अन्य कोई कारण है, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। यह मुद्दा उन्होंने लोकसभा में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई घर-परिवार नजर नहीं आ रहा, जहां कैंसर के मामले सामने न आ रहे हों, इसलिए समय रहते इस विषय पर शोध कर समाधान निकालना जरूरी है।

ईरान-अमेरिका तनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थीं, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने मजबूती से फैसले लेकर देश को संभाला था। देश में तेल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके



लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अंडरपास के मुद्दे पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला भी उन्होंने लोकसभा में उठाया है और रेल मंत्री से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अंडरपास और ओवरब्रिज जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध होनी

चाहिए थीं, लेकिन इनमें देरी होना आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद सत्यवान सेलवाल की माता चंद्रा देवी के निधन पर भी शोक व्यक्त करने के लिए शंकरपुरा पहुंचीं।

माँ के परसदार गुरुमुख सिंह भंगू, एयर मार्शल परमजीत सिंह भंगू, चंद्रहर्ष, राजेश भुयानी, लाल बहादुर खोवाल, करण सिंह नैन, कामरेड हरदीप सिंह, हरपाल सेलवाल, भगत सिंह खोवाल, हरजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह, जसवीर सिंह, सुबह सिंह, गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह, मनजीत सिंह, अमनदीप सिंह, ऋषिपाल सिंह, मलकीत सिंह, रिंकू, गगनदीप सिंह, रिंकू वर्मा, सोगवान बेदी, वीरेंद्र सेलवाल, ईश्वर सरपंच सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

## 75 वर्षिय माओवादी प्रशान्त बोस ने रांची जेल से दुनिया को अलविदा कहा

2021को सरायकेला जिले से हुई थी प्रशान्त उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस की मौत हो गई है। तीन अप्रैल की सुबह चार बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे और भाकपा माओवादी के शीर्ष पद पर थे। प्रशांत बोस की उम्र 75 साल से अधिक थी। जेल प्रशासन ने उनकी मौत के बाद शव को रिम्स भेजा दिया है। प्रशांत बोस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। नक्सली संगठन में प्रशांत बोस को किशन दा के नाम से जाना जाता था। किशन दा पहले एमसीसीआई के प्रमुख थे। साल 2004 में माओवादी कन्वेंशन सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) और पिपुल्स वार (PW) के विलय के बाद वह नये संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य बने थे। प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी भी नक्सली संगठन से जुड़ी हुई हैं। 21 नवंबर 2021 को झारखंड पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।



15 जवानों की हत्या 1 करोड़ इनामी